श्रीमति वी. राजेश्वरी

बनाम

टी. सी. सरवनबवा

16 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति आर. सी. लाहोटी और न्यायाधिपति अशोक भान]

पूर्व-न्याय - मुकदमे के चरण में आवश्यक अभिवचनों को उठाकर याचिका नहीं ली गई -उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में पहली बार ली गई याचिका -उच्च न्यायालय याचिका को बरकरार रखते हुए और मुकदमे को खारिज करते हुए- आयोजित, न्यायिक याचिका की नींव अभिवचनों में रखी जानी चाहिए और पिछले मामले में अभिवचनों, मुद्दों और/या निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत करके पुष्टि की गई-मुकदमे के चरण में ठीक से नहीं उठाई गई याचिका अपील के चरण में पहली बार उठाए जाने की अनुमति दी जाए-जिन तथ्यों पर विचार किया गया है, उनमें कोई पूर्व न्यायिकता नहीं है।

प्रतिकूल कब्जा- स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए वाद में प्रतिवादी द्वारा ली गई याचिका-सह-मालिक के रूप में हिस्सेदारी का दावा करने वाली वाद संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए पहले से ही मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति जो था खारिज किया गया- अभिवचन करने और

यह साबित करने में विफल रहने वाला व्यक्ति कि उसने सूट संपत्ति के संबंध में शत्रुतापूर्ण अधिकार कैसे और कब निर्धारित करना शुरू किया- माना गया , धारित संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल कब्जे की दलील निराधार है

अपीलार्थी-वादी ने 1817 फीट वर्ग किलोमीटर की सूट संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी के खिलाफ-वाद संपत्ति खरीदने के बाद प्रतिवादी। प्रतिवादी ने वादी के अधिकार से इनकार करते हुए लिखित बयान दायर किया और प्रतिकूल कब्जे की याचिका ली। सह-मालिक के रूप में मुकदमे की संपत्ति में आधे हिस्से का दावा करने वाले प्रतिवादी द्वारा दायर वादी के स्वामित्व वाले पूर्व पक्षकारों में से एक के खिलाफ विभाजन के लिए पहले का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया। तथापि, प्रथम अपीलीय न्यायालय में, वादी विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन करेगा जिसमें प्रतिवादी को इमारत के ऊपरी हिस्से (240 वर्ग फुट) पर कब्ज़ा देने का निर्देश दिया गया।) मुकदमे की संपत्ति में वादी को। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा की गई दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया और वादी के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मुकदमे के स्वामित्व और कब्जे के मुद्दे के बाद से पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। वादी के स्वामित्व के मामले में पूर्ववर्ती द्वारा दायर मुकदमे में संपत्ति

का फैसला पहले ही हो चुका था। वादी द्वारा दायर समीक्षा भी खारिज कर दी गई। इसलिए, वादी द्वारा वर्तमान अपील की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. पूर्व न्यायिकता का नियम अगले मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ पर प्रहार नहीं करता है। यह सार्वजनिक नीति पर आधारित निर्णय द्वारा रोक का नियम है कि मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देना चाहिए और किसी को भी एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। [933-बी-सी]

2. पुनर्न्यायिकता की दलील की नींव दलीलों में रखी जानी चाहिए और फिर एक मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए और उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। न केवल दलील देनी होती है, बल्कि पिछले मामले की दलीलों, मुद्दों और फैसले की प्रतियां पेश करके इसे प्रमाणित भी करना होता है। ऐसी दलीलों को केवल अटकलबाजी या कटौती की प्रक्रिया द्वारा यह अनुमान लगाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि पिछली दलीलों में क्या तथ्य बताए गए थे। मुकदमे के चरण में दलीलों या मुद्दों में उचित ढंग से नहीं उठाई गई दलील को पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अपील के चरण में समय. (933-डी-ई, 934-डी-ई]

गुरबक्स सिंह बनाम भुरालाल, [1964] 7 एस. सी. आर. 831;पंजाब राज्य बनाम बुआ दास कौशल, [1970] 3 एस. सी. सी.636; सैयद मोहम्मद सैली

लब्बई (मृत) एल. आर. एस. और अन्य बनाम मोहम्मद. हनीफा (मृत) एल. आर. एस. द्वारा और अन्य [1976] 4 एस. सी. सी. 780; (राजा) जगदीश चंद्र देव धबल देब बनाम गौर हरि महतो और अन्य, ए आई आर (1936) प्रिवी काउंसिल 258; मेदपति सुरैया और अन्य बनाम तोंडापु बाला गंगाधर रामकृष्ण रेड्डी और अन्य ए आई आर (1948) प्रिवी काउंसिल 3 और काली कृष्ण टैगोर बनाम भारत में राज्य सचिव परिषद और अन्य(1887-88) 15 भारतीय अपील 186 पर भरोसा किया गया।

कटरागड्डा चीन अंजनेयुलु और अन्य बनाम कटरागड्डा चीन रामय्या और अन्य ए. आई. आर. (1965) एपी 177 (पूर्ण पीठ), संदर्भित।

3. किसी दिए गए मामले के तथ्यों के आधार पर, याचिका को माफ किया जा सकता है, यदि इसे उचित स्तर पर और उचित तरीके से नहीं उठाया गया है। पूर्व न्याय की याचिका से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष इस धारणा पर आगे बढ़ सकता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने याचिका को उठाने में विफल रहने के कारण याचिका को माफ कर दिया है। (934-एफ-जी]

शाह शिवराज गोपालजी बनाम एडप्पाकथ आयिसा बी एंड ओआरएस ए आई आर (1949) प्रिवी काउंसिल, विशिष्ट।

प्रीतम कौर ने एस. मुकंद सिंह बनाम पेप्सू राज्य और अन्य ए आई आर(1963) पंजाब 9 (पूर्ण पीठ) और रजनी कुमार मित्रा और अन्य बनाम अजमद्दीन भुइया, ए आई आर (1929) कलकत्ता 163, अनुमोदित।

4. मान लीजिए कि मुकदमे में पूर्व न्याय के बारे में याचिका नहीं ली गई थी विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय आवश्यक अभिवचन उठाकर। प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रत्यर्थी ने दस्तावेजों से अवगत कराते हुए पूर्व न्याय के दायर करने का विकल्प नहीं चुना। उच्च न्यायालय को यह अनुमान लगाने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था कि मुद्दा क्या था और पिछले मुकदमे में क्या सुना और निर्णय लिया गया था। तथ्य यह है कि पहले का मुकदमा अब मुकदमे में पूरी संपत्ति के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था और संपत्ति के एक निर्दिष्ट हिस्से के बारे में निर्णय आवश्यक रूप से पूरी संपत्ति के लिए न्यायपालिका का गठन नहीं कर सकता था। जो अब मुकदमे का विषय था। यदि पूर्व न्याय की याचिका का लाभ उठाया जाना था और इसे लागू किया जाना था, तो यह वादी के लाभ के लिए होना चाहिए था, जितना कि उसका पूर्ववर्ती पहले के मुकदमे में संपत्ति के हिस्से पर अपना अधिकार साबित करने में सफल रहा था। कोई पूर्व न्याय नहीं है। इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा स्वामित्व के मुद्दे का सही निर्धारण किया गया था। उस खोज को पुनर्स्थापित करना होगा। [935 - बी-जी]

5. इससे पहले, प्रतिवादी ने खुद को वादी के पूर्ववर्तियों में से एक का दत्तक होने का दावा करते हुए, उसमें आधे हिस्से का दावा करते हुए विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया था। इस प्रकार, वह कब्जे में एक सह-मालिक के रूप में अपने दावे का प्रचार कर रहे थे। कैसे और किस

समय उन्होंने शत्रुतापूर्ण उपाधि निर्धारित करना शुरू किया, यह उनके लिए दलील देने और साबित करने के लिए था, जो वह करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रतिकूल कब्जे की याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [935 - जी-एच; 936-ए-बी]

6. जिस हद तक वादी के पूर्ववर्तियों ने भवन की ऊपरी मंजिल के 240 वर्ग फुट क्षेत्र पर स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए डिक्री हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, वादी को उस डिक्री को निष्पादित करके कब्जा सुरक्षित करना चाहिए। शेष संपत्ति के संबंध में, वादी को वर्तमान मुकदमे में डिक्री का हकदार माना जाना चाहिए। वादी को उक्त संपत्ति का शीर्षक स्वामी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी वादी को उस पर खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंप देगा। वादी को भी इसका हकदार माना जाता है मुकदमे की तारीख और डिक्री के अनुसार डिक्री-धारक को कब्जे की डिलीवरी की तारीख के बीच की अवधि के लिए सी.पी.सी. के आदेश XX नियम 12 (एल) (सी) के संदर्भ में मध्यवर्ती लाभ की जांच के लिए एक डिक्री का अनुसरण करेगा। (936-बी-ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 7653 /1999

समीक्षा में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 24.2.1997 के निर्णय एवं आदेश से सी.एम. 1996 की याचिका संख्या 119/1989 की एस.ए. संख्या

एस. ब्लाकृष्णन, सुश्री प्रांची बाजपेयी, एस. एन. झा और सुब्रमण्यम प्रसाद अपीलार्थी के लिए

प्रतिवादी के लिए ए. के. गंगुली, वी. बालचंद्रन और के. गोविंदन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति आर.सी. लाहोटी:

मुकदमे में संपत्ति में भवन, सुपर-स्ट्रक्चर और अन्य निर्माण के साथ भूमि का एक टुकड़ा शामिल है, जिसमें संपत्ति वाले घर और जमीन नंबर 9, पदवट्टमन कोइल सेंट, कोंडिथोप, मद्रास- I के कुएं और बाड़ शामिल हैं और ओ.एस. नंबर 6008 - आर.एस.ई. नंबर 20 और आर.एस. क्रमांक 2011 सी.सी. क्रमांक 8 पट्टा क्रमांक 461/1954-55 और माप 1817 वर्ग फुट। 19 अगस्त, 1984 की याचिका की अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है।

उन तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है, जो इस स्तर पर अब विवाद में नहीं हैं और नीचे दी गई अदालतों द्वारा तथ्य के निष्कर्षों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह संपत्ति मूल रूप से चक्रपाणि की थी, जिन्होंने इसे 13.6.1921 को खरीदा था। उन्होंने 8.5.1923 को एक दामोदरन के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया, दामोदरन ने 17.10.23 को थिरुनीलकंडा नैनार के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया। थिरुनीलाकांडा ने 1.5.1950 को अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे लोगा गणपति के पक्ष में एक समझौता पत्र निष्पादित किया। उन्होंने 3.3.1966

को महादेवन और उनकी पत्नी सरोजा के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। वादी, अपीलकर्ता ने दिनांक 10.3.1980 के विक्रय पत्र के अनुसार उनसे संपत्ति खरीदी।

वर्तमान मुकदमे के शुरू होने से पहले प्रतिवादी का संपूर्ण मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा था, मुकदमेबाजी के दो अन्य दौर हुए थे जो बहुत प्रासंगिक हैं और ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 1957 में, प्रतिवादी-प्रतिवादी ने 1957 का मूल मुकदमा संख्या 2512 दायर किया और मुकदमे की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करते हुए खुद को थिरुनीलाकांडा का दत्तक पुत्र होने का आरोप लगाया। मुक़दमा ख़ारिज कर दिया गया. उस मुकदमे को 8.1.1964 को अंतिम रूप मिला जब प्रतिवादी द्वारा की गई अपील को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

वर्ष 1965 में, वादी (यहां अपीलकर्ता) के पूर्ववर्तियों में से एक ने स्वामित्व की घोषणा और 240 वर्ग फीट से अधिक के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी के विरुद्ध क्षेत्र (मुकदमे की संपत्ति के ऊपर खड़ी इमारत की ऊपरी मंजिल पर स्थित)। 1965 का और परीक्षण के बाद 30.1.1968 पर फैसला सुनाया गया। फरमान को लागू कर दिया गया। 1975 की निष्पादन याचिका संख्या 2458 लंबित थी जब प्रतिवादी ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने वाले सिविल न्यायालयों में से एक द्वारा जारी निषेधाज्ञा को प्रस्तुत किया। निष्पादन न्यायालय ने स्वाभाविक रूप से निष्पादन की कार्यवाही को बंद कर दिया।

निषेधाज्ञा का आदेश और उसका विवरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। निष्पादन याचिका को किस संदर्भ में बंद किया गया था और उसके बाद इस तरह की निष्पादन कार्यवाही का क्या हुआ, यह भी अभिलेख से पता नहीं चलता है। इस तरह की जानकारी की खोज हमें वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने में रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ऐसी स्वतंत्र कार्यवाहियों में ध्यान रखा जाएगा जो इस निर्णय के दौरान इंगित किया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि इन अपीलों का निपटान कैसे किया जा रहा है।

19.8.1984 पर, अपीलार्थी ने प्रतिवादी से वाद संपत्ति पर अधिकार और अधिकार की वसूली के लिय वर्तमान मुकदमा दायर किया । 7.8.1985 पर, प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर किया। यहाँ यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि हालांकि प्रतिवादी ने वाद सम्पत्ति पर वादी के अधिकार से इनकार किया लेकिन ऐसी कोई दलील नहीं है कि मुकदमा लिखित बयान में लिए गए पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। लिखित कथन में ली गई एकमात्र अन्य याचिका प्रतिकूल अधिकार की है जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

"यह प्रतिवादी निर्धारित अवधि से अधिक समय से मुकदमे की संपत्ति पर निरंतर, निर्बाध, खुले कब्जे और आनंद में रहा है और इस प्रकार उसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार पूरा कर लिया है। इस प्रतिवादी का स्वयं के अधिकार में वाद संपत्ति पर कब्ज़ा है। यह प्रतिवादी निर्धारित अवधि से अधिक समय से सभी तीन

वर्षों के लिए मुकदमे की संपत्ति के लिए निगम कर, जल और सीवेज कर और शहरी भूमि कर का भुगतान कर रहा था।"

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी (इसमें अपीलकर्ता) ने सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 27 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें 1965 की ओ. एस. संख्या 1907 में निर्णय और डिक्री को अभिलेख पर रखने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी के पूर्ववर्तियों में से एक के पक्ष में एक डिक्री पारित की गई थी, जिसमें उसका अधिकार बरकरार रखा गया था और प्रतिवादी-प्रतिवादी को उस इमारत (240 वर्ग फुट क्षेत्र) की ऊपरी मंजिल पर कब्जा देने का निर्देश दिया गया था, जो तब प्रतिवादी के कब्जे में था, उसमें वादी (यानी वर्तमान वादी के पूर्ववर्ती के अधिकार में) को दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन निर्णय और डिक्री को वादी द्वारा अपने दावे को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने के लिए और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का समर्थन करने वाले साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लाया गया है जो पहले से ही उसके पक्ष में था। प्रथम अपीलार्थी अदालत ने वादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया, निर्णय और डिक्री को अभिलेख पर ले लिया और फिर प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील की।

उच्च न्यायालय में, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने एक बार फिर उसके पक्ष में नीचे दिए गए दो न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को बनाए रखने के लिए उक्त निर्णय और आदेश पर भरोसा किया है और यहाँ, उक्त निर्णय और डिक्री पर भरोसा रखने का उसका कदम उसके खिलाफ उल्टा पड़ा। उच्च न्यायालय ने एक राय बनाई कि मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व और कब्जे के मुद्दे पर पहले से ही निर्णय लिया गया था वादी के पूर्ववर्ती द्वारा दायर मुकदमा (1965 का ओ. एस. सं. 1907) और इसलिए वर्तमान वाद को न्यायिक निर्णय के सिद्धांत द्वारा वर्जित कर दिया गया था। केवल इस तर्क पर उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.4.1996 के फैसले के माध्यम से, प्रतिवादी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी है और वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय में प्रतिवादी वादी ने फैसले की समीक्षा की मांग की। अपने दिनांक 24.2.1997 आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका को खारिज करने का निर्देश दिया है। दो अपीलों को प्राथमिकता दी गई हैः एक मुख्य निर्णय के खिलाफ, और दूसरा पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ।

पूर्व न्यायिकता का नियम अगले मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ पर प्रहार नहीं करता है। यह सार्वजनिक नीति पर आधारित निर्णय द्वारा रोक का नियम है कि

मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देना चाहिए और किसी को भी एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायिक दलील कुछ तथ्यों के प्रमाण और फिर पाए गए तथ्यों पर कानून लागू करने पर आधारित होती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि दलील की नींव दलीलों में रखी जानी चाहिए और फिर एक मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए और उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मुकदमे के चरण में दलीलों या मुद्दों में उचित ढंग से नहीं उठाई गई याचिका को अपील के चरण में पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी (देखें: (राजा) जगदीश चंद्र देव धबल देब बनाम गौर हरि महतो एवं अन्य एआईआर (1936) प्रिवी काउंसिल 258; मेदापति सुरैया और अन्य बनाम टोंडापु बाला गंगाधर रामकृष्ण रेड्डी और अन्य एआईआर (एल-948) प्रिवी काउंसिल 3 और कतरागड्डा चीन अंजनेयुलु और अन्य बनाम कट्रगड्डा चीन रानुव्वा और अन्य एआईआर (1965)ए.पी. 177 पूर्ण पीठ) पंजाब राज्य बनाम बुआ दास कौशल [1970] 3 एससीसी 656 मामले में इस न्यायालय के समक्ष प्रिवी काउंसिल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा एक अपवाद बनाया गया था और याचिका को उठाने की अनुमति दी गई, हालांकि इसे दलीलों में शामिल नहीं किया गया और न ही किसी मुद्दे से कवर किया गया, क्योंकि आवश्यक तथ्य पार्टियों के दिमाग में मौजूद थे और विचारण न्यायालय द्वारा उन पर विचार किया गया था। विपरीत पक्ष के पास याचिका के खंडन

में साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायिक निर्णय का मुद्दा पूरे समय विचार और चर्चा में रहा है और इसलिए न्यायिक निर्णय से छूट की दलील या दलील की आवश्यकता को आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है न केवल दलील देनी होती है, बल्कि पिछले मामले की दलीलों, मुद्दों और फैसले की प्रतियां पेश करके इसे प्रमाणित भी करना होता है। किसी दिए गए मामले में हो सकता है कि पिछले मुकदमे में केवल फैसले की प्रति ही न्यायिक दलील के सबूत के रूप में दायर की गई हो और फैसले में दलीलों और मुद्दों के विस्तृत या अपेक्षित विवरण शामिल हों जिन्हें पर्याप्त सबूत के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि सैयद मोध में बताया गया है। सैली लब्बाई (मृत) एलआरएस द्वारा एवं अन्य बनाम मोहम्मद हनीफा (मृत) एलआरएस द्वारा और अन्य[1976] 4 सेकंड 780, पुनर्न्याय के प्रश्न को तय करने की मूल विधि सबसे पहले पार्टियों के मामले को उनके पिछले मुकदमे की संबंधित दलीलों में आगे निर्धारित करना है और फिर यह पता लगाना है कि क्या निर्णय लिया गया था वह निर्णय जो पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य करता है। निर्णय में उल्लिखित दलीलों में लगाए गए आरोपों के सारांश मात्र से दलीलों के बारे में अटकलें लगाना जोखिम भरा है। गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल, [1964] 7 एससीआर 831 में संविधान पीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 2 के तहत पुनर्न्यायिकता की याचिका और निष्कासन की याचिका को एक समान रखते हुए कहा कि पिछले मुकदमे में वाद का प्रमाण जो प्रतिबंध बनाने के लिए निर्धारित किया गया है,की

उसको रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। याचिका मूल रूप से दो मुकदमों में कार्यवाही के कारण की पहचान पर आधारित है और इसलिए, यह बचाव पक्ष के लिए आवश्यक है जो पिछले मुकदमे में कार्रवाई का कारण स्थापित करने के लिए रोक। इस तरह की दलीलों को केवल अटकलों या किसी प्रक्रिया द्वारा अनुमान लगाने पर नहीं छोड़ा जा सकता है।कटौती करें कि पिछले अभिवचनों में क्या तथ्य बताए गए थे। काली कृष्ण टैगोर बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव और अन्य, (1887-88) 15 भारतीय अपील 186 में प्रिवी काउंसिल के आधिपत्य ने बताया कि पुनर्न्याय की दलील यह सुनिश्चित किए बिना निर्धारित नहीं की जा सकती कि मुद्दों में क्या मुद्दे थे पिछले मुकदमे में और क्या सुना गया और निर्णय लिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इन्हें पिछले मुकदमे की दलीलों, मुद्दों और फैसले को देखकर ही पता लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, किसी दिए गए मामले के तथ्यों के आधार पर याचिका को माफ किया जा सकता है, अगर इसे उचित स्तर पर और उचित तरीके से नहीं उठाया गया हो। पूर्व न्याय की याचिका से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष इस धारणा पर आगे बढ़ सकता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने याचिका को उठाने में विफल रहने के कारण याचिका को माफ कर दिया है। प्रीतम कौर पत्नी एस मुकंद सिंह बनाम पेप्सू राज्य और अन्य, एआईआर (1963) पंजाब 9 (पूर्ण पीठ) और रजनी कुमार मित्रा और अन्य बनाम अजमद्दीन भुइया, एआईआर 1929 कलकत्ता 163 का संदर्भ लिया जा सकता है, और हम स्वयं

को इस बिंदु पर उसमें लिए गए दृष्टिकोण से सहमत पाते हैं)। ऐसा प्रतीत होता है कि शा शिवराज कोपलजी बनाम एडप्पाकाथ आयिसा बी और अन्य एआईआर (1949) प्रिवी काउंसिल 302 में प्रिवी काउंसिल के फैसले ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व न्याय की याचिका विचारण न्यायालय में उठाई गई थी, हालांकि, इसे दबाया नहीं गया था लेकिन इसे दूसरी अपील के चरण में दोहराया जाने की मांग की गई थी। उनके आधिपत्य ने माना कि कानून में एक शुद्ध याचिका होने के कारण यह अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध है। उनके आधिपत्य की यह भी राय थी कि उस मामले के तथ्यों में, पूर्व न्यायिक सिद्धांत के अलावा, उसी वाद को नई कार्यवाही में नवीनीकृत करना अनुचित था। प्रिवी काउंसिल का निर्णय अलग है।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, स्वीकार्य रूप से याचिका विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलार्थी न्यायालय में आवश्यक अभिवचनों को उठाकर, प्रथम अपील न्यायालय में पुनः न्यायिक विवरण नहीं लिया गया था। वादी ने साक्ष्य के रूप में पिछले मुकदमे में निर्णय और डिक्री को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की, जिसमें उसका पूर्ववर्ती एक पक्षकार था। वह यह आग्रह करना चाहते थे कि केवल वे दस्तावेजों की श्रृंखला द्वारा मुक़दमे की संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में सफल रहे थे, लेकिन पिछले फैसले ने जो इसी मुक़दमे की संपत्ति के एक हिस्से से संबंधित था, उनके पूर्ववर्ती के अधिकार को भी बरकरार रखा था जिसने

उनके मामले को प्रोत्साहित किया। दस्तावेज़ों से अवगत होने के बाद भी प्रतिवादी ने पूर्व न्याय की याचिका दायर करने का विकल्प नहीं चुना। उच्च न्यायालय को यह अनुमान लगाने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था कि मुद्दा क्या था और पिछले मुकदमे में क्या सुना और निर्णय लिया गया था। तथ्य यह है कि पहले का मुकदमा अब मुकदमे में पूरी संपत्ति के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था और संपत्ति के एक निर्दिष्ट हिस्से के बारे में निर्णय आवश्यक रूप से पूरी संपत्ति की लिए न्यायिक निर्णय का गठन नहीं कर सकता था, जो अब मुकदमे का विषय थी।

हम यह देखने से खुद को रोक नहीं सकते हैं कि यदि पुनर्निर्णय की दलील का लाभ उठाया जाना था और उसे लागू किया जाना था, तो यह वादी के लाभ के लिए होना चाहिए था, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती-अधिकारी अपने स्वामित्व को आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहे थे।पहले के मुकदमे में संपत्ति के हिस्से का अधिकार। हम यह समझने में विफल हैं कि पिछले मुकदमे का निर्णय किसी भी तरह से प्रतिवादी को वर्तमान कार्यवाही में कैसे मदद कर सकता है। हमारा स्पष्ट मत है कि न्यायनिर्णायक की याचिका न तो उठाई गई है और न ही साबित की गई है। वहाँ कोई पूर्व न्याय नहीं है इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा स्वामित्व के मुद्दे का सही निर्धारण किया गया था। उस खोज को पुनर्स्थापित करना होगा

मुकदमे पर प्रतिकूल कब्जे के बारे में याचिका के साथ भी ऐसा ही मामला है।प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में ली गई संपत्ति। याचिका की पुष्टि नहीं की गई है और यह सही भी है। याचिका बहुत अस्पष्ट है। इससे पहले प्रतिवादी, जो खुद को पूर्वजों में से एक का गोद लिया हुआ बेटा होने का दावा करता है वादी ने आधे हिस्से का दावा करते हुए विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया था।इस प्रकार, वह कब्जे में एक सह-मालिक के रूप में अपने दावे का प्रचार कर रहा था। कैसे और किस समय उन्होंने शत्रुतापूर्ण स्वामित्व निर्धारित करना शुरू किया, यह उनके लिए दलील देने और साबित करने के लिए था, जो वह करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रतिकूल कब्जे की याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कानून की सही स्थिति, जो मामले के तथ्यों पर लागू होनी चाहिए अब कहा जा सकता है। जिस हद तक वादी के पूर्व-स्वामी भवन की ऊपरी मंजिल के 240 वर्ग फुट क्षेत्र में स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए डिक्री हासिल करने में सफल रहे हैं, वादी को उस डिक्री को निष्पादित करके कब्जा हासिल करना चाहिए। शेष संपत्ति के बारे में, वादी को वर्तमान वाद में एक डिक्री का हकदार माना जाना चाहिए। तदनुसार, दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और नीचे के न्यायालयों के निर्णय को आंशिक रूप से बहाल कर दिया जाता है। वादी द्वारा दायर वाद वाद

संपत्ति के संबंध में अभिनिर्धारित होगा जैसा कि वाद में वर्णित है, जिसमें 1965 के मूल वाद संख्या 1907 में डिक्री का विषय बनाने वाले भवन की ऊपरी मंजिल के 240 वर्ग फुट क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। वादी को उक्त संपत्ति का स्वामित्व स्वामी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी वादी को उस पर खाली और शांतिपूर्ण कब्जा देगा। वादी को सी. पी. सी. के आदेश XX नियम 12 (1) (सी) के संदर्भ में अपने लाभ की जांच के लिए एक डिक्री का भी हकदार माना जाता है, इस डिक्री के अनुसार वाद की तारीख और डिक्री धारक को कब्जा देने की तारीख के बीच की अवधि के लिए। उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप, विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री तैयार की जाएगी। पूरा खर्च प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा वहन किया जाएगा।

ए के टी।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।